कर रखते हैं। मैं as a solo dancer 90 देशों में गई हूं, हम दो-ढाई घंटे तक audience को पकड़ कर रखते हैं। अब वह सब खत्म हो रहा है। Group choreographies हो रही हैं, जैसे टीवी और बॉलिवुड की फिल्म्स में देखते हैं। यह हमारा यूएसपी है, इसके लिए खास institute होने चाहिए। जो आठ शास्त्रीय विधाएं हैं, उनमें सोलो डांस को सीखने के लिए institute होने चाहिए। यदि यह मर जाएगी, क्षीण होती जाएगी, if we allow this to die, a huge part of our cultural heritage will also die. मैं सरकार से मांग करती हूं कि 200, 500, 1,500 कलाकार तो हैं, लेकिन जो एक कलाकार की तपस्या, साधना और उसकी कला है, हमारी इस हैरिटेज को, इस धरोहर को हम मरने न दें। ...(**समय की घंटी**)... मैं मांग करती हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following Members associated themselves with the submission made by Dr. Sonal Mansingh: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), ShriPabitra Margherita (Assam), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhan), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri Rakesh Sinha (Nominated).

Demand to direct NAFED to take suitable measures for processing the procured Copra and to market the coconut oil as Bharat Coconut Oil

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, the Union Government's agency, NAFED, procured copra coconuts from farmers at Rs. 108 per kilogram and keeping a stock of 1 lakh metric tons from Tamil Nadu alone. It comes to only 10 per cent of total copra production. The remaining 90 per cent of coconuts is sold in the open market.

Copra price in Tamil Nadu has come down from Rs. 90 to Rs. 85 per kg. Taking advantage of the offer for sale through auction by NAFED, big companies formed into syndicate/cartel and planned to bid at Rs. 65 per kg. This brings the cost of copra per kg further down to Rs. 50 per kg and the price of coconut will come down from Rs. 12 to Rs. 5 in the market.

Once this happens, the coconut farmers will be severely affected and they will be at a heavy loss. To protect against such move, the South India Farmers' Association is staging a protest at Jantar Mantar, New Delhi, demanding that the Government agency itself should process and market coconut oil.

Sir, NAFED is procuring wheat from farmers and selling wheat flour under the name 'Bharat Aata.' They also buy dal and sell under the name 'Bharat Dal' and onion under the name 'Bharat Onion.' Therefore, on behalf of the Indian coconut farmers

and their associations, I am urging the Government to make efforts to introduce Bharat Coconut Oil by directing NAFED to get copra processed and sold to public. This way, both farmers and general public will be benefited by removing the middlemen. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following Members associated themselves with the submission made by Shri Vaiko: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. V. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Ms. Dola Sen (West Bengal).

Need for increased funds for biodiversity conservation in the Chilika Lake

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the permission. यह एक बहुत important topic है, जो ओडिशा से रिलेट करता है। 'India's best kept secret' जो हमारे ओडिशा के टूरिज्म की टैग लाइन है। एशिया में सबसे बड़ी brackish water lake यह चिल्का लगून है। मैं इसके संदर्भ में कहना चाहती हूं - despite being the first Indian site to be declared as wetland of importance under the Ramsar Convention in 1971, the status of biodiversity in Asia's largest brackish water lagoon, Chilika, is under threat. अभी देखा जाए, तो चिल्का लेक में बहुत सारे साइबेरियन बड्र्स आते हैं और अभी चिल्का में विंटर सीज़न चल रहा है। वहां पर बहुत सारे माइग्रेटेड बड्र्स रेस्टिंग के लिए आते हैं । चिल्का लेक उनके लिए बहुत पसंदीदा जगह है। अगर देखा जाए, तो वहां पर ईरानी डॉल्फिन भी है। चिल्का लेक का ठीक से संरक्षण करने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए, उसकी बायोडायवर्सिटी संरक्षित करने के लिए यह एक वेटलैंड भी है। केंद्र सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2022-23 में 30.51 करोड़ रुपए वेंटलैंड को कन्ज़र्व करने के लिए दिए गए हैं। अगर देखा जाए, तो चिल्का लेक के लिए या किसी भी वेटलैंड के लिए एक भी पैसे का प्रावधान नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है? हम टूरिज़्म के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वेटलैंड को संरक्षित करने की बात करते हैं, तो उसमें चिल्का लेक पहले आती है, क्योंकि वह एशिया का सबसे largest brackish water lagoon है। पहले से, फैनी के टाइम से तो चिल्का लेक बहुत मुश्किल में थी, अगर हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा, जितना पैसा उसके संरक्षण के लिए चाहिए, तो यह कार्य कैसे होगा? ओडिशा गवर्नमेंट की जो चिल्का लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वह बहुत सारे काम खुद कर रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वह ज्यादा से ज्यादा इसके लिए सेंट्रल असिस्टेंस दे, जिससे कि हम लोग इसको संभाल कर रख सकें, इसकी बॉयोडायवर्सिटी को संरक्षित कर सकें। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्तप्राय हैं, जो सिर्फ चिल्का लेक में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं, उनको हम सहेज कर रख सकें। अभी हम बोल रहे थे कि यह बर्ड रेस्टिंग का पॉइंट होता है, जहां पर विदेश के पक्षी आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ